ue added for construction of weighting diagrammes. Japan, however, also construction a weighing diagram on the basis of value of gross output for the purpose of it additional IIP series. While the item-coverage provided by CSO includes 352 items covering mining, manufacturing and electricity generation, USA and Japan cover respectively 255 and 530 items encompassing mining, manufacturing and electricity as well as gas utility industry.

Estimates of the State Domestic Products

3228. SHRI JAGIR SINGH DARD: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the comparable estimates of the State Domestic Product for 1992-93 would be available in May 1995 as assured by the Department of Statistics;

(b) if so, what is the preparation made by the Department with respect to the schedule of preparations of these estimates, for the purpose of its early publication;

(c) whether the Department has sought additional staff for this and if so how much;

(d) whether the modern gadgets being made use of by the Department help in advancing the schedule of preparation; and

(e) whether copies of this Data will be made available to Members of Parliament?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) The provisional estimates will be made available to the Planning Commission in May 1995.

(b) Discussions on the subject with the States have been advanced by six month. This exercise is expected to be completed in April 1995 instead of in October 1995.

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) The comparable estimates of State Domestic Product are prepared at the specific instance of the Planning Commission and the Finance Commission. These estimates can be made available to others after they have served their primary purpose.

शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या

3229. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 3 वर्षों के दौरान देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने और शिक्षित बेरोजगार पैदा हो जाने की संभावना है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ङ) क्या शिक्षित बेरोजगारों को 1993-94 के अंत तक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाना था; और

(च) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान कितने शिक्षित बेरोजगारों को अब तक रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) से (च) आठवीं योजना के प्रारंभ में शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी 7 मिलियन अनुमानित की गई थी, आठवीं योजना अवधि के दौरान 35 मिलियन शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के श्रम दल में शामिल हो जाने की संभावना है और आठवीं योजना में 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना हैं जिनसे शिक्षित और अशिक्षित दोनों को लाभ होगा । अस्थाई अनुमानों के अनुसार योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 19.6 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना हैं । शिक्षित और अशिक्षितों के उपरोक्त विभिन्न अनुमानों का खुलासा नहीं किया गया है ।

Food Security for the Country

3230. SHRI VIREN J. SHAH:

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has undertaken a major exercise to provide food security for the country;

(b) if so, what are the details of this exercise; and

(c) when is this exercise expected to be completed and when the action on the implementation of the desired steps is likely to be initiated?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) and (b) Planning is in the process of preparing a paper on 'alternative strategies' of providing food security to the people. Various options are being considered. The details are yet to be worked out.

(c) The Planning Commission would shortly finalise the paper on food security and discuss it with the concerned Ministries in the Centre and the Governments in the States before taking the final decision. No time frame for taking the final decision has been fixed.

उत्तर प्रदेश की लम्बित योजनाएं

3231. **प्रो. राम बक्श सिंह वर्मा** : **क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं तथा योनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की सम्भावना हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमग) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार डेयरी विकास, भूतल परिवहन, विद्युत, सिंचाई, उच्च शिक्षा, उद्योग आदि से संबंधित कई प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित होने की रिपोर्ट है ।

(ग) चूंकि परियोजनाएं और स्कीमें कई केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देखी जा रही हैं इसलिए स्कीमों की संस्वीकृति के संबंध में समय सूचित करना कठिन होगा ।